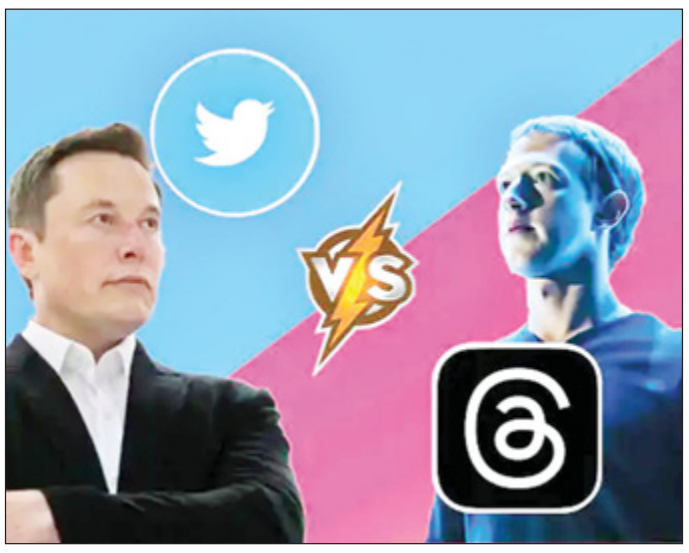

थ्रेड्स को 4 घंटों में 50 लाख यूजर मिले : लॉन्च के 2 घंटे बाद ही यह संख्या 20 लाख हो गई थी, इसे कहा जा रहा ट्विटर किलर

वॉशिंगटन।

सोशल मीडिया फर्म मेटा के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने बुधवार रात नई माइक्रो ब्लागिंग साइट थ्रेड्स को लॉन्च किया। इसे ट्विटर का कॉम्पिटिटर माना जा रहा है। कुछ यूजर्स इसे ट्विटर किलर भी नाम दे रहे हैं। ट्विटर के दुनियाभर में 100 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बताया कि सिर्फ दो घंटों में थ्रेड्स से 20 लाख लोग जुड़ गए। चार घंटे बाद इसकी संख्या बढ़कर 50 लाख के पार पहुंच गई। इसे अभी 100 देशों में लॉन्च किया गया है। यूरोपियन यूनियन में रेगुलेटरी चिंताओं की वजह से इसे लॉन्च नहीं किया गया है। ट्विटर की तरह ये भी टेक्स्ट-बेस्ड प्लेटफॉर्म है। इस पर 500 कैरेक्टर तक लंबे थ्रेड्स पोस्ट पब्लिश कर सकते हैं। इस पर लिंक, फोटो और वीडियो भी शेयर किए जा सकते हैं। वीडियो 5 मिनट तक लंबे हो सकते हैं। बुधवार रात करीब 11.30 बजे इसे लॉन्च किया गया है।

कम्युनिटीज करंट और ट्रेंडिंग दोनों टॉपिक्स पर चर्चा कर सकेंगी - इस नए ऐप के जरिए कम्युनिटीज करंट और ट्रेंडिंग दोनों टॉपिक्स पर चर्चा करने के लिए एक साथ आ सकते हैं। इसके जरिए आप अपने फेवरेट क्रिएटर्स के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। अपने आइडिया और ओपिनियन को शेयर कर आप अपनी एक लॉयल फॉलोइंग भी बिल्ड कर सकते हैं। ये ऐप आपकी फाइनेंशियल इंफो, कॉन्टेक्ट इंफो जैसा डेटा कलेक्ट करता है। इंस्टाग्राम के हेड एडम मोसेरी ने कहा कि एलन मस्क के अंडर ट्विटर की अस्थिरता और अप्रत्याशितता ने मेटा को ट्विटर के साथ कॉम्पिटिशन करने का मौका दिया।

थ्रेड्स अकाउंट डिलीट करने के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करना होगा - मेटा के इस नए प्लेटफॉर्म थ्रेड्स के इस्तेमाल के लिए कोई वेबसाइट नहीं है। अभी इसे केवल ऐप के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। वहीं थ्रेड्स प्रोफाइल बनाने के बाद अगर आप इसका इस्तेमाल बंद करना चाहते हैं तो इसे डिएक्टिवेट करना होगा। क्योंकि ये इंस्टाग्राम के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए इसे अकेले डिलीट नहीं कर सकते। इसे डिलीट करने के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट को भी डिलीट करना होगा।

थ्रेड ऐप के कारण मस्क और जुकरबर्ग के बीच केज फाइट - बीते दिनों जुकरबर्ग की कंपनी मेटा ने ट्विटर जैसा प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की बात कही थी। इसके बाद डेली मेल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसकी हेडलाइन थी- ट्विटर को खत्म करने का जुकरबर्ग का मास्टर प्लान सामने आया। इस रिपोर्ट को ट्विटर पर शेयर किया जाने लगा।

न्यूज ब्रीफ

वंदे भारत ट्रेनों का किराया 30प्रतिशत तक घट सकता है: कम दूरी वाले रूट पर यात्री कम; इंदौर-भोपाल, भोपाल-जबलपुर रूट सिर्फ 29प्रतिशत पैसेंजर्स

नई दिल्ली। वंदे भारत ट्रेन में यात्रा करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे कम दूरी और कम यात्री वाली कुछ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया घटाने पर विचार कर रहा है। छोटी दूरी वाली कुछ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सीटें पूरी तरह फुल नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में किराए का रिव्यू किया जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि 25प्रतिशत से 30प्रतिशत किराया कम हो सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इंदौर-भोपाल, भोपाल-जबलपुर और नागपुर-बिलासपुर एक्सप्रेस समेत अन्य वंदे भारत ट्रेनों के किराए में कमी होने के आसार हैं। जून में भोपाल-जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस में केवल 29प्रतिशत सीटें भरी रिपोर्ट के मुताबिक, जून महीने में भोपाल-जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस में केवल 29प्रतिशत सीट ही भरी हुई थीं। वहीं, इंदौर-भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस में केवल 21प्रतिशत ऑक्यूपेंसी रही। भोपाल से जबलपुर तक एसी चेयर का किराया 1,055 है, जबकि एग्जीक्यूटिव चेयर कार टिकट की कीमत 1,880 है। हालांकि, वापसी में इसका किराया अलग है। इसमें एक एसी चेयर के लिए 955 और एक एग्जीक्यूटिव चेयर कार के लिए 1790 का टिकट है। इसके अलावा इंदौर से भोपाल तक एसी चेयर का किराया 810 और एग्जीक्यूटिव चेयर कार टिकट की कीमत 1,510 है। नागपुर-बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस की करीब 55प्रतिशत सीटें ही फुल हो पा रही हैं। नागपुर-बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस से एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 2,045 रुपए है, जबकि चेयर कार का किराया 1,075 रुपए है।

देश में 10प्रतिशत बढ़ी वाहनों की बिक्री: जून-2023 में 18.63 लाख वाहन बिके, मारुति ने सबसे ज्यादा कारें बेचीं

नई दिल्ली। भारत में वाहनों की ओवरऑल रिटेल सेल्स में 10प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

जून-2023 में देशभर में 18,63,868 व्हीकल बेचे गए, जबकि पिछले साल इसी महीने में 17,01,105 व्हीकल बेचे गए थे। इनमें पैसेंजर व्हीकल और टू-व्हीलर शामिल हैं। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने गुरुवार (6 जुलाई) को जून 2023 में वाहनों की रिटेल सेल्स के आंकड़े जारी किए हैं। फाडा के अध्यक्ष मनीष राज सिंघानिया ने कहा कि सालाना आधार पर वाहनों की रिटेल सेल्स 10प्रतिशत बढ़ी है। वहीं दूसरी ओर मंथ-ऑन-मंथ बेस पर रिटेल सेल्स में 8प्रतिशत की गिरावट आई है। यह थोड़े समय के लिए वाहन बाजार में नरमी का इशारा करता है। जून में पैसेंजर व्हीकल की रिटेल सेल्स 5प्रतिशत बढ़कर 2,95,299 इकाई पर पहुंच गई है। जून-2022 में इंडियन मार्केट में 2,81,811 पैसेंजर व्हीकल बेचे गए थे। इसी तरह पिछले महीने टूव्हीलर्स की सेल्स 7प्रतिशत बढ़कर 13,10,186 यूनिट्स पर पहुंच गई। एक साल पहले जून में 12,27,149 दोपहिया बिके थे। थ्री व्हीलर्स की सेल्स पिछले साल जून के 49,299 यूनिट्स से 75प्रतिशत बढ़कर 86,511 यूनिट हो गई। ट्रैक्टरों की रिटेल सेल्स सालाना आधार पर 45प्रतिशत बढ़कर 98,660 इकाई हो गई, जबकि कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री जून-2022 के 72,894 इकाई के आंकड़े से मामूली बढ़ोतरी के साथ 73,212 इकाई रही।

जीएसटी पंजीकरण में इजाफा, पंजीकृत करदाताओं की संख्या 67.83 लाख से बढ़कर 1.40 करोड़ हुई

नई दिल्ली। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (एसोचैम) की ओर से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के छह वर्ष पूरे होने पर 'ट्रांसफॉर्मिंग द इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम' विषय पर बुधवार को राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान एसोचैम ने जीएसटी सिफारिशों पर एक पेपर जारी किया। सम्मेलन में वित्त मंत्रालय के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के विशेष सचिव व जीएसटी के सदस्य शशांक प्रिया ने कहा कि अनुपालन में सुधार जीएसटी राजस्व बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2023-2024 के कार्यप्रणाली में प्रतिमाह औसतन 1.69 लाख करोड़ राजस्व अर्जित कर रहे हैं। राजस्व दर के अनुरूप कर दरों में वृद्धि किए बिना राजस्व बढ़ रहा है। जीएसटी शुरू होने के समय पंजीकृत करदाताओं की संख्या 67.83 लाख थी, जो अब 1.40 करोड़ पहुंच गई है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क के सीईओ मनीष कुमार सिन्हा ने कहा कि जीएसटी एक ऐसा डाटा तैयार करके देता है, जिसमें कोई बिंदु नहीं होता है। देश में हो रही कर चोरी को रोकने के लिए सरकार जीएसटी लाई है।

टाटा स्टील ने 38 एम्प्लॉइज को निकाला

एथिकल इश्यूज के चलते गई नौकरियां, कंपनी के चेयरमैन बोले- एथिक्स हमारी प्रायोरिटी

नई दिल्ली।

टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा स्टील ने सेक्सुअल हैरेसमेंट और एथिकल इश्यूज से जुड़ी अन-एक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेस के चलते 38 एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल दिया है। कंपनी के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन ने बुधवार (5 जुलाई) को एनुअल जनरल मीटिंग में इस बात की जानकारी दी।

टाटा स्टील को पिछले साल 875 शिकायतें मिलीं थीं

टाटा स्टील को पिछले साल 875 शिकायतें मिलीं थीं। जिनमें से 158 व्हिसिलब्लोअर, 48 सेफ्टी और 669 ह्यूमन रिसोर्स और बिहेवियर से जुड़ी शिकायतें थीं। यह सभी शिकायतें स्टैंडअलोन टाटा स्टील के अलावा भारत और विदेश में इसकी सहायक कंपनियों में की गई थीं।

शिकायतों में से हमने 38 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है

कंपनी की एजीएम में चंद्रशेखरन ने कहा, इन शिकायतों में से हमने 38 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिन्हें कंपनी से बर्खास्त कर दिया गया है। 3 को सेक्सुअल हैरेसमेंट और 35 एम्प्लॉइज को एथिकल इश्यूज से जुड़ी अन-एक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेस के कारण नौकरी से निकाला गया है।

हम हाईएस्ट वैल्यूज और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को बनाए रखेंगे

चंद्रशेखरन ने कहा, कंपनी के रूप में हम एक ग्लोबल बेंचमार्क हैं। इसलिए हम कंपनी में एक ऐसे कल्चर को बढ़ावा देना जारी रखेंगे, जहां हम हाईएस्ट वैल्यूज और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को बनाए रखेंगे। चन्द्रशेखरन ने कहा कि रिपोर्ट की गई शिकायतों की संख्या में ग्रोथ देखी जा सकती है, जो एक अच्छी बात है।

टाटा स्टील ने पिछले कुछ सालों में कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए हैं

नटराजन चंद्रशेखरन ने कहा, टाटा स्टील ने पिछले कुछ सालों में कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए हैं। हम

तीन या चार कंपनियों का विलय भी कर रहे हैं। जिसमें भूषण (स्टील), उषा मार्टिन और नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड के नाम शामिल हैं। इन सभी कंपनियों का विलय हो रहा है। उन्होंने कहा, हम एक ओपन कल्चर की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हर कर्मचारी किसी भी क्षेत्र में अपनी चिंता व्यक्त कर सकता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट, एम्प्लॉई ग्रीवेंस या कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है, जो उन्हें लगता है कि कंपनी के लिए वो गलत है, तो एम्प्लॉई शिकायत कर सकता है। इन चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए हम बोर्ड में सभी को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

सेफ्टी हमारी प्राथमिकता, इसके लिए 50 लोगों की एक टीम बनाई है

चंद्रशेखरन ने कहा कि सेफ्टी हमारी प्राथमिकता है। यह कमेंट्स पिछले महीने ओडिशा के ढेंकनाल जिले में टाटा स्टील के मेरामंडली पावर प्लांट में स्टीम लीक होने के बाद आए हैं, जिसमें कुछ वर्कर्स घायल हो गए थे।उन्होंने कहा, हर इंडस्ट्रियल कंपनी में सेफ्टी के कारण हाई लेवल का रिस्क होता है, क्योंकि वे फैक्ट्री सेट-अप में काम करते हैं। जिसमें मशीनरी, माल की आवाजाही शामिल होती है और वे बड़ी संख्या में कॉन्ट्रैक्टर्स को भी नियुक्त करते हैं। इसलिए हमने कई कदम उठाए हैं। चंद्रशेखरन कहा कि लगभग 50 लोगों की एक टीम है, जिसमें ग्रुप की टॉप कंपनियों के सीईओ, की-लीडर्स और सेफ्टी टीमों के लोग शामिल हैं। यह सभी दो साल में शून्य मृत्यु दर का टारगेट हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं।

एक चीफ सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त करने पर विचार कर रहा है ग्रुप

चंद्रशेखरन ने कहा, वे न केवल आपस में जुड़ते हैं, बल्कि बेस्ट प्रैक्टिस प्राप्त करने के लिए इंटरनेशनल टीमों के साथ भी जुड़ते हैं और यह प्रोसेस जारी है। दुर्भाग्य से हमारे पास अभी भी मृत्यु दर हैं और मानवीय भूल के कारण कई बार ये मौतें होना दुखद है। ग्रुप कंपनियों में सेफ्टी के महत्व को बढ़ाने के लिए एक चीफ सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त करने पर विचार कर रहा है।

चाहे एथिक्स हो या सेफ्टी, पूरे ग्रुप में हमारे लिए ये सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं

उन्होंने कहा, चाहे एथिक्स हो या सेफ्टी हो, ये पूरे ग्रुप में हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। इसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं और उम्मीद है कि हम इसे ज्यादा से ज्यादा कल्चर में शामिल करेंगे। उन्होंने कहा, जैसा कि हम नई कंपनियों का विस्तार और अधिग्रहण कर रहे हैं, उनके एकीकरण के लिए इन चीजों को मजबूत करने की आवश्यकता होगी।

इस्तीफा दे चुके चेयरमैन दीपक पारेख का 45 साल पुराना ऑफर लेटर वायरल

मुंबई।

एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के बीच विलय के बाद इसके चेयरमैन दीपक पारेख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं उन्होंने ग्रुप के कर्मचारियों के साथ एक भावनात्मक चिट्ठी भी साझा की। इस बीच एचडीएफसी बैंक में उनके पहले ऑफर लेटर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस चिट्ठी की तारीख 19 जुलाई 1978 है और इसमें पारेख की तनख्वाह से लेकर उनके अनुबंध तक की जानकारी दी गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पारेख के इस कथित ऑफर लेटर की सत्यापन नहीं करता। इस लेटर के मुताबिक, एचडीएफसी बैंक में उनकी नियुक्ति डिप्टी जनरल मैनेजर के तौर पर हुई थी। पारेख को 3500 रुपये की बेसिक सैलरी और 500 रुपये का महंगाई भत्ता मिलना तय किया गया था। 45 साल पुराने इस लेटर में के मुताबिक, उनकी सैलरी में 15 फीसदी हाउसिंग रेंट अलाउंस (एचआरए) और 10 फीसदी शहरी मुआवजा भत्ता (सीसीए) शामिल थे। 78 वर्षीय दीपक पारेख को एचडीएफसी बैंक में कॉरपोरेशन प्रोविडेंट फंड, ग्रैच्युटी, मेडिकल लाभ, यात्रा सुविधाएं और घर पर लगे फोन का खर्च भी मुहैया कराने से जुड़ी जानकारी इस लेटर में हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के बैंकों के लिए उम्र से जुड़े नियम बनाने की वजह से एचडीएफसी में 45 साल लंबे करियर के बाद अब पारेख बैंक के बोर्ड में भी नहीं होंगे। पारेख को पांच कंपनियों को सार्वजनिक करने के लिए भी श्रेय दिया जाता है। इतना ही नहीं एचडीएफसी ने उनके नेतृत्व में 90 लाख से ज्यादा भारतीयों को होम लोन मुहैया कराए हैं। एचडीएफसी बैंक ने पिछले साल 4 अप्रैल को लगभग 40 अरब डॉलर के सौदे में सबसे बड़े घरेलू बंधक ऋणदाता का अधिग्रहण करने पर सहमति व्यक्त की थी। प्रस्तावित इकाई का संयुक्त परिसंपत्ति आधार करीब 18 लाख करोड़ रुपये होगा। इसके बाद ही दीपक पारेख ने बोर्ड की आखिरी बैठक में कहा था कि अब संन्यास लेने का समय आ गया है। अब हम विकास और समृद्धि के रोमांचक भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। समूह के स्वामित्व की कमान बैंक के हाथ में आने से एचडीएफसी बैंक व समूह की कंपनियों के बीच तालमेल गहरा होगा। एचडीएफसी बैंक होम लोन ग्राहकों को बेहतर सेवा देगा।

मुंबई, दिल्ली समेत 5 शहरों में ओएनडीसी लॉन्च: खरीदारी के लिए अलग-अलग ऐप की जरूरत नहीं, प्राइस कंपेयर कर प्रोडक्ट खरीद सकते हैं

नई दिल्ली।

डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क ने 5 शहर मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में अपना बीटा फेज गुरुवार को लॉन्च किया। नए शहर जुड़ने के बाद अब ओएनडीसी नेटवर्क भारत के सात शहरों में बायर्स और सेलर्स के लिए उपलब्ध है। सबसे पहले सितंबर 2022 में इसे बेंगलुरु में लॉन्च किया गया था। फिर दिसंबर 2022 में मेरठ में ये लाइव हुआ। इसमें खरीदारी के लिए अमेजन, फ्लिपकार्ट, जोमैटो जैसे अलग-अलग ऐप की जरूरत नहीं है। आप यहां प्राइस कंपेयर कर कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं।

पेटीएम जैसे ऐप्स के जरिए यूज कर सकते हैं ओएनडीसी

इन सात शहरों के कंज्यूमर अब पेटीएम, मायस्टोर, स्पाइस मनी और मैजिकपिन जैसे चार एक्टिव बायर एप्लीकेशन के जरिए ओएनडीसी नेटवर्क पर सेलर्स से खरीदारी कर सकेंगे। वर्तमान में इस नेटवर्क से 200 से ज्यादा शहरों में करीब 40,000 सेलर्स जुड़े हुए हैं।

अप्रैल 2022 में पांच शहरों में अल्फा रोलआउट हुआ था

ओएनडीसी ने सेलर्स और बायर्स के एक क्लोज्ड ग्रुप के साथ लाइव ट्रांजैक्शन की टेस्टिंग करने के लिए अप्रैल 2022 में पांच शहरों में अपना अल्फा रोल-आउट किया था। अब बीटा लाइव होने का मुख्य कारण यूजर्स को ओपन नेटर्व का एक्सपीरियंस कराना, रियल टाइम फीडबैक लेना और पूरे भारत में रोल-आउट से पहले बड़े पैमाने पर नेटवर्क का टेस्ट करना है।

बीटा लाइव के बाद ज्यादा से ज्यादा बिजनेस जुड़ेंगे

ओएनडीसी के एमडी और सीईओ टी कोशी ने कहा, हमें उम्मीद है कि इस बीटा लाइव के बाद ज्यादा से ज्यादा बिजनेस हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा, जैसे-जैसे हम ज्यदा कंज्यूमर्स तक पहुंचेंगे वैसे-वैसे हमें नेटवर्क को इंप्रूव करने में मदद मिलेगी। किसी एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने ओएनडीसी की शुरुआत की है।

डेबिट-क्रेडिट कार्ड का कहीं भी उपयोग कर सकेंगे ग्राहक, आरबीआई के नए नियम से रुपे कार्ड को मिलेगा बढ़ावा

नई दिल्ली।

अब डेबिट और क्रेडिट कार्ड का उपयोग कहीं भी किया जा सकेगा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा है कि कार्ड खास नेटवर्क के लिए जारी नहीं किया जाएगा। इसे सभी नेटवर्क पर इस्तेमाल करने की छूट होनी चाहिए। इस संबंध में इन कार्डों के नियमों के बदलाव संबंधी प्रस्ताव जारी किया गया है। यह एक अक्तूबर से लागू हो सकता है। आरबीआई ने इस प्रस्ताव पर आम लोगों से राय मांगी है। केंद्रीय बैंक के इस फैसले के बाद डेबिट, प्री-पेड कार्ड के नियम बदल सकते हैं। आरबीआई का मकसद कार्ड नेटवर्क की भूमिका मर्चेंट (दुकानदार) और कार्ड जारीकर्ताओं के बीच लेनदेन को सुविधाजनक बनाना है। अभी तक ऐसा होता है कि कुछ क्रेडिट या डेबिट कार्ड कहीं-कहीं नहीं चलते हैं। ऐसा आमतौर पर मर्चेंट (दुकानदारों) के साथ भुगतान के समय होता है। कुछ क्रेडिट कार्ड केवल चुनिंदा दुकानदारों के साथ ही स्वैप

हो सकते हैं। हर मर्चेंट सभी नेटवर्क स्वीकार नहीं करता है। कहीं वीजा कार्ड नहीं चलता है तो कहीं मास्टर कार्ड नहीं चलता है।

रुपे कार्ड को मिलेगा बढ़ावा

सरकार की ओर से रुपे कार्ड को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई नए नियम ला रहा है। क्योंकि अमेरिकी वीजा और मास्टरकार्ड ही आमतौर पर कार्ड सुविधाएं उपलब्ध कराती है। साथ ही इनके नेटवर्क में रुपे कार्ड का प्रवेश नहीं होता है। कार्ड जारीकर्ता अपने ग्राहकों को कई कार्ड नेटवर्कों में से किसी एक को चुनने का विकल्प प्रदान करेंगे। इस विकल्प का उपयोग ग्राहक या तो जारी होने के समय या उसके बाद किसी भी वक्त कर सकते हैं।

एक से अधिक नेटवर्क पर जारी करना होगा कार्ड

आरबीआई ने कहा, समीक्षा करने पर यह पाया गया कि कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ताओं (बैंकों और गैर-बैंकों) के बीच मौजूद व्यवस्थाएं ग्राहकों के लिए विकल्प की उपलब्धता के लिए अनुकूल नहीं हैं। कार्ड जारीकर्ताओं को कार्ड नेटवर्क के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं करना चाहिए जो ग्राहकों को अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता हो। कार्ड जारीकर्ता एक से अधिक कार्ड नेटवर्क पर कार्ड जारी करेंगे। आरबीआई रुपये के अंतराष्ट्रीयकरण को लेकर अंतर विभागीय समूह की रिपोर्ट का अध्ययन करेगा। आरबीआई ने रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है।

गो-फर्स्ट को लीज पर विमान देने-वालों को हाईकोर्ट से राहत

कोर्ट ने विमानों की निगरानी और मेंटेनेंस की अनुमति दी, दो महीने से बंद हैं फ्लाइट्स

नई दिल्ली।

कैश की तंगी से करीब दो महीने से बंद पड़ी एयरलाइन गो फर्स्ट को लीज पर विमान देने वाली कंपनियों यानी लेसर्स को दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने लेसर्स को अपने 30 विमानों की निगरानी और मेंटेनेंस करने की परमिशन दे दी है।

कोर्ट ने इस मामले में अंतरिम ऑर्डर जारी किया है। इसमें जस्टिस तारा वी गंजु ने कहा, गो फर्स्ट के कर्मचारी, विमान लीज पर देने वाली कंपनियों की अनुमति के बिना विमानों से जुड़ा कोई काम नहीं करेंगे। ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि विमान काफी महंगे और तकनीकी रूप से जटिल हैं, इनको नियमित तौर पर मेंटेमेंटेनेंस की जरूरत है। बेंच ने कहा कि लेसर्स को रिट पिटीशन के फाइनल डिस्पोजल तक अंतरिम रखरखाव करने के लिए महीने में कम से कम दो बार अपने विमान तक एक्सेस मिलेगा। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए और संबंधित एयरपोर्ट अथारिटीज ये एक्सेस देंगे।

हाई कोर्ट ने डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन और एयरपोर्ट्स से पूछा कि एयरलाइन के विमान कहां रखे गए हैं, ताकि अगले 3 दिनों में कंपनियां अपने विमानों तक पहुंच सकें। इस मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। इससे पहले गो फर्स्ट के क्रेडिटर्स ने एयरलाइन रिवाइवल के लिए 425 करोड़ रुपए की अंतरिम फंडिंग को मंजूरी दी थी। गो फर्स्ट ने जुलाई में ऑपरेशन फिर से शुरू करने और 22 विमानों के साथ 78 डेली फ्लाइट ऑपरेट करने का प्लान बनाया है।

कंपनियों ने विमानों को रिलीज करने की मांग की

एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनियों में पेमब्रोक एविएशन, एक्सिपिटर इनवेस्टमेंट्स एयरक्राफ्ट्स 2 लिमिटेड, ईओएस एविएशन और एसएमबीसी एविएशन शामिल हैं। कंपनियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उन विमानों को रिलीज करने की मांग की थी, जो गो फर्स्ट को लीज पर दिए गए थे। एनसीएलएटी ने 22 मई को एनसीएलटी के उस ऑर्डर को भी सही ठहराया था, जिसके तहत दिवालिया घोषित करने के लिए गो फर्स्ट की याचिका स्वीकार की गई थी।

पूरा मामला समझें

गो फर्स्ट एयरलाइन ने 2 मई को बताया कि वो 3, 4 और 5 मई के लिए अपनी सभी फ्लाइट कैंसिल कर रही है। 3 मई को एयरलाइन स्वैच्छिक दिवालिया याचिका के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी पहुंच गई। गो फर्स्ट एयरलाइन की याचिका पर एनसीएलटी ने 4 मई को सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। फ्लाइट सस्पेंशन को 9 मई किया गया। फिर कई बार इसे बढ़ाया गया। अभी फ्लाइट 10 जुलाई तक सस्पेंड है। 10 मई को एनसीएलटी ने एयरलाइन को राहत देते हुए मोरेटोरियम की मांग को मान लिया और आईआरपी नियुक्त किया।

अभिलाष लाल को आईआरपी नियुक्त किया था

जस्टिस रामलिंगम सुधाकर और रूह गुप्ता की दो सदस्यीय बेंच ने कर्ज में डूबी गो फर्स्ट को चलाने के लिए अभिलाष लाल को इंटरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल यानी आईआरपी नियुक्त किया था। यह पहली बार था जब किसी भारतीय एयरलाइन ने खुद से ही अपने कॉन्ट्रेक्ट और कर्ज को रिनेगोशिएट करने के लिए बैंकरप्सी प्रोट्रेक्शन की मांग की थी।

लेसर्स ने इंटरिम मोरेटोरियम की मांग पर आपत्ति जताई थी

इससे पहले एयरलाइन की इंटरिम मोरेटोरियम की मांग पर 4 मई को एनसीएलटी ने पहली सुनवाई की थी। इस दौरान गो फर्स्ट को लीज पर एयरक्राफ्ट देने वाली फर्म्स ने एनसीएलटी से कहा था कि उन्हें एयरलाइन की इंटरिम मोरेटोरियम की मांग पर आपत्ति है। मोरेटोरियम के गंभीर परिणाम होंगे। लेसर्स ने जस्टिस रामलिंगम सुधाकर की अगुआई वाली बेंच को बताया था कि उन्होंने लीज को खत्म कर दिया है और वे विमान वापस पाने के हकदार हैं। लेसर्स ने कहा था कि मेंटेनेंस और अन्य खर्चों को लेकर भी गो फर्स्ट का रिकॉर्ड ठीक नहीं हैं। यदि गो फर्स्ट को मोरेटोरियम राहत दी जाती है, तो वे अपने ग्राउंडेड विमान को वापस नहीं ले पाएंगे। गो फर्स्ट की वेबसाइट के अनुसार एयरलाइन एक समय रोजाना 27 डोमेस्टिक और 8 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के लिए 200 से ज्यादा फ्लाइट ऑपरेट करती थी।

मेसर्स दैनिक नईदुनिया के लिए प्रकाशक अपूर्व तिवारी के द्वारा 43/आर-3 स्नेह नगर रोड, गोपालगंज सागर (म.प्र.) - 470001 से प्रकाशित एवं मुद्रक डॉ. विश्वास तिवारी के द्वारा नईदुनिया प. प्रा.लि., 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल-462011 से मुद्रित। प्रबंध संपादक : डॉ. सुरेन्द्र तिवारी एवं संपादक : अपूर्व तिवारी। *
भोपाल कार्यालय फोन-0755-2550900-01,-03, फैक्स नं.- 0755-2553914 e-mail : naidunia@gmail.com(* समाचार पत्र से संबंधित सभी प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र सिर्फ भोपाल होगा।) आर.एन.आई. रजि. क्र. MPHIN/2015/61503, डाक पंजीयन क्र. म.प्र./भोपाल/296/2015-2017